because insanitary *katras* and dangerous buildings continue to remain. The residents of these slums hardly get their share among the newly-built houses, with the result that the slums stand where they were, and the object of development of Delhi has been achieved more in multiplication of the problems, rather than in finding their solution.

I shall urge the Government to examine whether the object for which DDA was formed, has been achieved, and whether the Master Plan prepared for the benefit and development of Delhi has done any good to Delhi; whether the miseries of Delhi's slum dwellers have been tackled; whether the DDA is more a dealer in real estate, or is a developing authority, and whether the first Master Plan has really helped in removal of Delhi's slums; and if it feels satisfied that something needs to be done, then arrange for a Master Plan for the walled city only separately, to solve and remove the slum conditions of the city.

(vii) Installation of Thermal Electricity Project at Rajakkamanglam, Kanyakumari.

SHRI N. DENNIS (Nagercoil) : Installation of a thermal electricity project at Rajakkamanglam in Kanyakumari district is a long-standing need of the place. Investigations regarding the feasibility of the scheme have been conducted by an on-the-spot study by the Chief Engineer, Tamil Nadu Electricity Board, the Port Officer, Tamil Nadu and other concerned authorities; and a suitable site has also been identified, which is mainly Government land previously used for salt manufacture and now defunct and declared unfit and kept waste; and thereby, this land, along with portions of adjoining areas, adequate and sufficient to meet the requirements of the project, could be made available; and that too, easily without payment of huge compensatory cost. Infra-structural facilities and other circumstances are also favourable for its installation. Nagercoil railway station and Colachel Port are 10 Km. and 6 Km. respectively from this place. The proposed rail link to Colachel Harbour touches this place. Kanyakumari district has been declared as an industrially backward district. Not even a single industry, either in the public sector or private sector, is established in this backward, isolated, distant southern-most part of this country, where there is acute problem of unemployment, both educated and un-educated. Installation of this project would satisfy the long-standing aspirations of the people of this backward area.

So, Government may be pleased to take speedy steps for the early implementation of this project.

15.18 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF INDUSTRIES DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT ORDINANCE

AND

INDUSTRIES (DEVELOPMENT AND REGULATION) AMENDMENT BILL — *Contd.*

MR. DEPUTY SPEAKER : We now take up further consideration of the following motion moved by Shri Narayan Datt Tiwari on the 1st March, 1984, namely :

> "That the Bill further to amend the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, be taken into Consideration."

Hon. Members, we have got about 1 hour 30 minutes for this Bill. We have got another 15 minutes before the private Members' Business is taken up. (*Interruptions*) I am only making a request. The decision will be yours. So, I would request the Members to cooperate.

I am addressing these remarks only to Mr. Vyas. Now Mr. Vyas.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल जिक्र कर रहा था

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

उन यूनिट्स के बारे में जो बड़े उद्योग-पतियों के द्वारा चलाये जाते हैं। मैंने आपके सामने एक उदाहरण रखा था बिड़ला मिल्स के बारे में। बिड़ला मिल्स वालों ने क्या किया है, उन्होंने टेक्सटाईल मिल के पोरशन को तो बन्द कर दिया है क्योंकि उसमें प्राफिट नहीं होता था और कपड़ा रंगने का काम अपनी तरफ से चालू कर दिया, जिसकी वजह से हजारों मजदूरों के रोजगार का नुकसान हुआ और स्माल स्केल इंडस्ट्री में जो व्यवस्था होनी चाहिए, वहां इसके जरिए से कमाई का सिलसिला चलाया जा रहा है। इस मिल ने जो प्रावधान किया है ऐसे लोगों का भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और लाइसेंस भी दिया जा सकता है, तो मेरी प्रार्थना है कि जब आप स्माल सेक्टर को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो उसमें मल्टी नेशनल्स को शामिल करना ठीक नहीं है। इस लिए मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें जिससे मल्टी नेशनल्स को स्माल सैक्टर में आने से रोक सकें तभी गरीबों को एमप्लायमेंट मिल सकता है।

इस प्रकार से और भी दूसरी यूनिट्स हैं जिनको आपने स्माल सैक्टर में रखा है, 872 आइटम आपने रखे हैं जिनके लिए भी टाटा, मोदी आदि को लाइसेन्स दिये हैं, जैसे साबुन बनाने, टायलट, तेल, क्रीम बनाने, टूथ पेस्ट बनाने का लाइसेन्स, जो कि स्माल स्केल सैक्टर में आने चाहिएं, ऐसे क्षेत्र में भी अगर आप मल्टी नेशनल्स को लाइसेंस देंगे तो उनकी मोनोपली बराबर बढ़ती जायेगी और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को जो आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं वह नहीं मिल पायेगा। इसलिए इस व्यवस्था को रोकने की जरूरत है। और जितने भी बड़े-बड़े लोगों को स्माल सैक्टर में आने वाले विषयों के सम्बन्धों में लाइसेंस दिया है, जो इस बिल में प्रावधान है कि यह बराबर चालू रहेंगे जिन्होंने इस बिल के आने से पहले व्यवस्था कर ली है, ऐसा नहीं होना चाहिये।

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी): ऐसा नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास: अगर नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर है तो उसको समाप्त किया जाना चाहिए।

मेरा तीसरा सुझाव है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बचाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि बड़े लोग उनके सैक्टर में प्रवेश कर रहे हैं। जब तक सरकार का उनको प्रोटेक्शन नहीं होगा तब तक वह प्रोत्साहित नहीं हो पायेंगी। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि जो फौड्यूलेंट लोग घुस जाते हैं और वित्तीय संस्थाओं से पैसा ले लेते हैं, उसको रोकना चाहिए। मेरे जिले में 50 परसेंट स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के अन्दर लोगों ने राजस्थान स्टेट फाइनेंशियल कोरपोरेशन से पैसा ले लिया लेकिन उन्होंने काम शुरू नहीं किया और अगर शुरू किया भी तो वह यूनिट सिक हो गई। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जेनुइन लोग ही इस काम में आने चाहिए जो उद्योग धन्धों को बढ़ाने में और आवश्यक आइटम बनाने में सहयोग करें। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि उसकी सारी व्यवस्था ठीक से चल सके।

इनफ्रास्ट्रक्चर जो उनको प्राप्त होना चाहिए वह मुश्किल से मिलते हैं, चाहे जमीन हो, बिजली हो, पानी हो या लोन हो। यह

चीजें जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक हैं वह अगर समय पर मिल जायें, जैसा कि आपने विचार किया है कि एक ही काउन्टर पर सब चीजें मिलें तो बहुत अच्छा रहे। इसी तरह से रा-मैटीरियल के सम्बन्ध में भी आवश्यक व्यवस्था हो जाए तो निश्चित तरीके से स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा। कई कई लोग दो साल तक चक्कर मारते रहते हैं और उनको आवश्यक चीजें नहीं मिलती हैं। और उसके बाद हर चीज प्राप्त करने के लिये भ्रष्टाचार सामने आ जाता है। बिना कुछ पैसा लिए-दिए बिना बिजली, पानी, जमीन, लोन नहीं मिलता है। इन चीजों को रोकने के लिए आपको पूरी निगरानी बरतनी पड़ेगी ताकि लोगों को कठिनाई न हो। व्यवस्था आप कर रहे हैं, लेकिन उसको ऐसा व्यवस्थित कीजिए जिससे लोगों को इस प्रकार की कठिनाई न हो। उनको जो लोन मिलता है, उस पर इन्टरेस्ट ज्यादा लगता है। हम कई जगह गये। हर जगह स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के लोगों ने हमारे सामने अपना रिप्रैजेन्टेशन दिया है कि सौफ्ट लोन बड़ी-बड़ी कम्पनी को दे देते हैं, छोटी कम्पनीज को यह नहीं मिलता है। कम इन्टरेस्ट पर लोन नहीं मिलता है। जब सरकार इनको प्रोत्साहन दे रही है तो सोफ्ट लोन इनको भी मिलना चाहिए ताकि ईजीली ये लोग भी अपना काम चला सकें।

टैक्सेशन और एक्साइज ड्यूटी के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जब स्माल स्केल सैक्टर को आप प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तो उनके उपयोग में आने वाली आइटमों पर टैक्सेशन में रियायत मिलनी चाहिए, उनको जो रा-मैटीरियल मिलता है उसमें भी रियायत मिलनी चाहिए।

कल एक सदस्य ने बीड़ी के सम्बन्ध में सुझाव दिया था। यह उद्योग स्माल सैक्टर में आता है लेकिन कई जगह बड़े-बड़े उद्योगपति इसमें चले गये हैं और वह गरीबों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए इसे भी रोकने की आवश्यकता है ताकि छोटे लोगों को इस प्रकार से अपना काम करने में कठिनाई न हो।

मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को एजूकेटेड पर्सन्स के लिए सैल्फ एम्पलायमेंट का एक कार्यक्रम चलाया था, इस प्वाइंट पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपके डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्रीज आफिस में भी इनके सम्बन्ध में सलैक्शन प्रापर्ली नहीं होता है। उनमें अगर इलैक्टेड रिप्रैजेन्टेटिव्ज कुछ सुझाव देते हैं तो उन पर कोई तवज्जह नहीं दी जाती। जो उनके द्वारा चुन लिये जाते हैं उनको बैंक लोन मिलने में भी दिक्कत होती है। इसलिए इस कार्यक्रम को कामयाब बनाना नितान्त आवश्यक है। प्रधान मंत्री ने इस कार्यक्रम को इसलिए दिया था कि एजूकेटेड यूथ को सैल्फ इम्पलायमेंट मिले और लोगों में व्याप्त असंतोष समाप्त हो जाये। ऐसे दृष्टिकोण से जो कार्यक्रम होते हैं, तो जो बैंक के प्रतिनिधि वहां बैठते हैं, उनके द्वारा बैंक से यदि पैसा मिलता है तो उसमें अड़चनें पैदा न हों। इसलिए इस कार्यक्रम को सब को मिलकर चलाना चाहिए। एम०पी० और एम०एल०ए० जो जन-प्रतिनिधि हैं, उनकी बात को भी निश्चित तरीके से वजन दिया जाना चाहिए और साथ-ही-साथ बैंक की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे काम ठीक हो सके।

अभी होता क्या है कि स्माल सैक्टर में ऐसे लोग घुस गये हैं जो पैसा लेकर उसका

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

दुरुपयोग करते हैं जिससे जरूरतमन्दों को कोई फायदा नहीं पहुंचता है और सरकार के पैसे का भयंकर दुरुपयोग होता है। बैंक का मैनेजर या इंडस्ट्रीज के अधिकारी इन गलत लोगों के द्वारा पैसा प्राप्त करके अपनी गरीबी को दूर करने का प्रयास कर लेंगे। इसलिए कोई माकूल व्यवस्था इस सम्बन्ध में बनाई जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

15.30 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

Sixty-Ninth Report

SHRI R.P. DAS (Krishnagar) : I beg to move :

"That this House do agree with the Sixty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the Ist March, 1984".

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That this House do agree with the Sixty-ninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the Ist March, 1984".

The Motion was adopted.

15.31 hrs.

RESOLUTION RE : UNEMPLOYMENT

MR. DEPUTY SPEAKER : Now we take up further discussion on the following Resolution moved by Shri T. S. Negi on 16th December, 1983 :

"That this House expresses its concern over the growing unemployment in the country and urges upon the Government to take immediate steps to raise a land army of unemployed persons to take up—

(a) the work of deepending the riverbeds of major rivers :

(b) the afforestation programme throughout the country including Himalayan region in such a way as to cover atleast one-third part of the land;

(c) extensive land conservation programme ;

(d) linking of major rivers of the country ;

and recommends that Government should pay an unemployment allowance of at least Rs. 100/- per month to all unemployed persons."

Shri Uttam Rathod.

SHRI UTTAM RATHOD (Hingoli) : The Resolution which is being discussed is of vital importance. As you are aware, in our country we have not been able to provide employment to the labour and also to the educated unemployed youth. The political thinkers and economists who have come from developing countries like Dr. Mahbool Haq, have stressed that the developing countries will have to take care of unemployment problem that will come up in their country first. This particular problem is to be divided under two categories. First of all, we will have to think of the rural labour and secondly those of educated unemployed youth.

Regarding the first one, after independence we have seen that our country has taken up big irrigation projects and we have brought large areas under cultivation. You must have seen that in areas where irrigation is available, the employment even for rural labour is not only available but wages are also on the